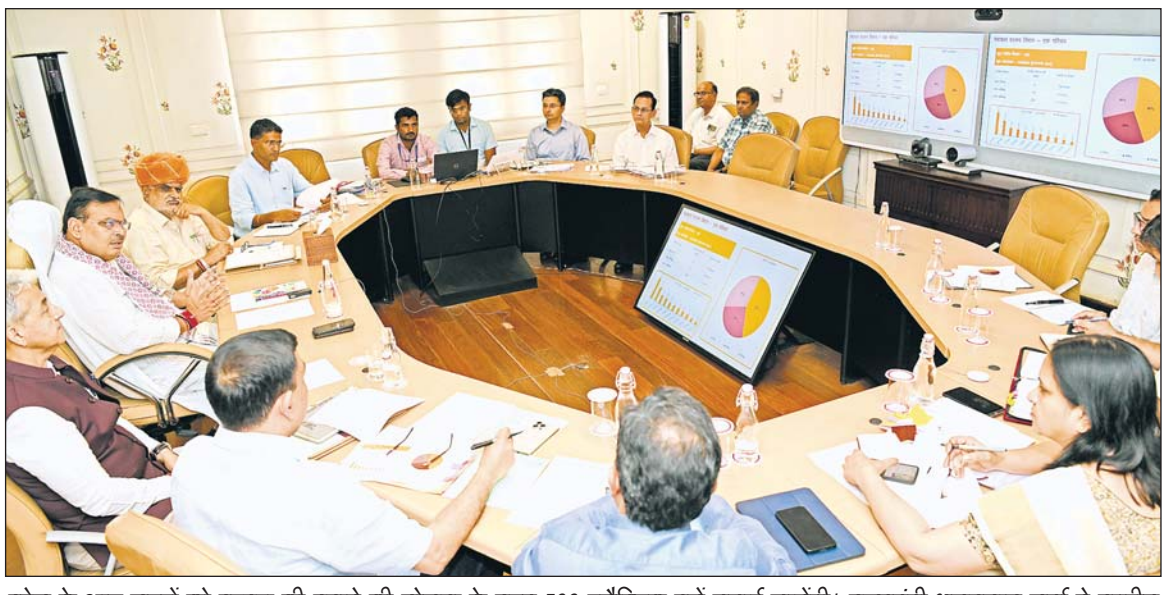

प्रदेश के आठ शहरों को प्रदूषण फ्री बनाने की योजना के तहत 500 इलैक्ट्रिक बसें चलाई जायेंगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नगरीय विकास व आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ शनिवार को हुई समीक्षा बैठक में कई नवीन योजनायें संचालित करने व पुरानी योजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिये। इसके अलावा बैठक में 106 स्थानों पर 223 करोड़ रूपये की लागत से सॉलिड वेस्ट प्रोसैसिंग प्लांट तैयार करने का भी निर्णय लिया गया।

'हाईटैक सिटी के निर्माण के लिए जे.डी.ए. कार्ययोजना बनाए'

मुख्यमंत्री भजनलाल ने नगरीय विकास व आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए यह भी कहा कहा कि, नगर निकायों में संचालित विकास परियोजनाओं को समय से पूरा करें

- **मुख्यमंत्री ने कहा कि, शहरी क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए आरंभ की गई प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत राजस्थान में 8 शहरों में 500 बसें चलाई जाएंगी।**
- **बैठक में नगर विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा, मुख्य सचिव सुधांश पंत, प्रमुख शासन सचिव टी. रविकांत सहित अन्य बड़े अधिकारी मौजूद थे।**

जयपुर, 22 जून। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में नगरीय विकास व आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित किया और उन्होंने प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में उपलब्ध संपत्ति का उपयोग कर अपनी आय बढ़ाने हाईटैक सिटी निर्माण के लिए जे.डी.ए. को कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया। साथ ही, उन्होंने स्वायत्त शासन विभाग को नगरीय विकास कर संग्रहण प्रणाली को बेहतर बनाकर राजस्व आय बढ़ाने के लिए कार्ययोजना बनाने के लिए निर्देशित किया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के शहरी निकायों में विकास कार्यों व योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आमजन की जरूरत के अनुसार विकास परियोजनाओं के माध्यम से आधारभूत ढांचे विकसित किए जा रहे हैं। पानी, बिजली, सड़क की सहज उपलब्धता के जरिए संस्थागत रूप से शहरी विकास को सुनिश्चित किया जा रहा है।

शर्मा ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत बनाए जाने वाले आवासों के लिए केन्द्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर स्वीकृति जारी करवाएं। उन्होंने प्रदेश में चल रही केन्द्र व राज्य सरकार की संयुक्त वित्त पोषित परियोजनाओं को समय से पूरा करने के लिए राज्य सरकार के अंशदान को निश्चित समय से जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने, चल रहे विकास कार्यों का भी समय-समय पर सत्यापन कराने और विकास कार्यों की डेली रिपोर्ट तैयार करने के भी निर्देश दिए और अमृत 2.0 योजना के रिव्यू करने के लिए नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव को कहा।

शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ई-बस सेवा प्रारंभ की गई है। मुख्यमंत्री शर्मा ने इस योजना के तहत राजस्थान के 8 शहरों (जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा, अलवर और बीकानेर) में कुल 500 ई-बसों को चलाने की योजना को जल्द मूर्तरूप देने के निर्देश दिए। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत प्रदेश में कुल 2 करोड़ 56 लाख 86 हजार 708 जरूरतमंद लोग लाभान्वित हुए हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत प्रदेश में जनवरी 2024 से अब तक 33 हजार लोगों को लोन मिल चुका है।

मुख्यमंत्री ने बैठक में जयपुर विकास प्राधिकरण की पूर्ण एवं प्रगतिरत विकास परियोजनाओं समीक्षा की। शर्मा ने जेडीसी मंजू राजपाल को निर्देशित किया कि सैक्टर रोड़ बनाने के कार्य में तीव्रता लाई जाए। उन्होंने हाइटैक सिटी के निर्माण के लिए जे.डी.सी. को कार्ययोजना तैयार करने, एयरपोर्ट से टोंक रोड एवं आगरा रिंग रोड कनैक्टिविटी व रेलवे स्टेशन से सीकर रोड तक कनैक्टिविटी के लिए एलिवेटेड रोड का प्लान तैयार करने के निर्देश दिए।

बैठक में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री झाबर सिंह खर्रा, मुख्य सचिव सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) शिखर अग्रवाल, प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) आलोक गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास एवं आवासन टी. रविकान्त, आयुक्त सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार इन्द्रजीत सिंह सहित नगरीय विकास व आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

बजरी कारोबारी मेघराज सिंह के ठिकानों पर सी.बी.आई. के छापे

सी.बी.आई. की टीमों ने जयपुर, भीलवाड़ा, टोंक, सवाईमाधोपुर, नागौर, भरतपुर सहित 14 ठिकानों पर कार्रवाई की

- **चार महीने पहले भी ई.डी. की टीम ने मेघराज सिंह के ठिकानों पर कार्रवाई की थी।**
- **हालांकि, मेघराज सिंह ने मीडिया में अपना नाम आने के बाद एक लेटर जारी कर अपने किसी भी ठिकाने पर सी.बी.आई. की रेड से इंकार किया है।**

जयपुर/टोंक/भीलवाड़ा, 22 जून (निसं)। सैन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सी.बी.आई.) ने बजरी कारोबारी मेघराज सिंह रॉयल (मेघराज ग्रुप) के अलग-अलग 14 ठिकानों पर शनिवार को छापेमारी करते हुए कई दस्तावेज सहित अन्य वस्तुयें जब्त की है। सी.बी.आई. की टीम जयपुर में ग्रुप के दो सौ फीट बायपास के पास स्थित ऑफिस समेत चौदह ठिकानों पर छापेमारी है। इनमें मेघराज सिंह के घर, चौमूं सर्किल स्थित ऑफिस, टोंक, भीलवाड़ा, भरतपुर, सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा और नागौर स्थित ऑफिस भी शामिल हैं। ऑफिस में मौजूद सभी कागजों की जांच की जा रही है।

सूत्रों के अनुसार एन्फोसेमैन्ट डायरैक्टोरेट (ई.डी.) को इस केस में मेघराज सिंह ग्रुप के खिलाफ कई सबूत मिले थे। इसके बाद ई.डी. ने दिल्ली ऑफिस में मेघराज सिंह सहित ग्रुप के अन्य लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया था। अधिकांश लोग ई.डी. कार्यालय नहीं पहुंचे थे। इसके बाद इस केस पर आगे कार्रवाई के लिए सी.बी.आई. ने प्लान बनाया। दोनों एजेंसियां इस केस पर अलग-अलग एंगल से काम कर रही हैं। इसी के तहत सी.बी.आई. इस ग्रुप पर कई समय से नज़र बनाए हुए थी। छापेमारी के दौरान भीलवाड़ा में लीज धारक संजय गर्ग के कार्यालय पर कार्रवाई की। इसी तरह टोंक जिले के धांधोली स्थिति एस.आर. एसोसिएट्स के ऑफिस में भी कार्रवाई की गई है। सी.बी.आई. ने अपनी तीसरी कार्रवाई जहाजपुर में शेखावत एसोसिएट के ऑफिस में की। सी.बी.आई. के अधिकारी सभी ठिकानों पर लगातार तलाशी अभियान चलाकर पूछताछ करने में जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि, छापे में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, 20 लाख रुपए नकद और हथियार मिले हैं।

भीलवाड़ा संवाददाता के अनुसार:- भीलवाड़ा में भी सी.बी.आई. ने सुखड़िया नगर के दफ्तर पर चार घंटे तक जांच पड़ताल की। इसके अलावा उसके सुखाड़िया सर्किल के पास स्थित आवास में चल रहे दफ्तर पर रेड की। जहां करीब 8 घंटे तक सी.बी.आई. के अधिकारियों ने जांच पड़ताल की। हालांकि, मेघराज सिंह ने मीडिया में अपना नाम आने के बाद एक लेटर जारी कर अपने ठिकानों पर सी.बी.आई. की रेड से इंकार किया है। मेघराज सिंह ने पत्र में लिखा कि मेरे या मेरे किसी भी परिसर में सी.बी.आई. की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई हैं। उधर, सी.बी.आई. की इस कार्रवाई से बजरी माफियाओं में हड़कम्प पर मच गया हैं। इसके बाद से सभी इधर-उधर हो गए हैं।

गौरतलब है कि, चौदह फरवरी को मेघराज ग्रुप के ठिकानों पर ई.डी. ने भी छापेमारी की थी। जयपुर समेत पचास जगहों पर ई.डी. की टीम ने रेड की थी। इस दौरान ई.डी. के अधिकारियों ने डिजिटल सबूत, मोबाइल फोन, हार्ड डिस्क और 35 लाख की नकदी सीज की थीं तीन दिन चली इस रेड में मेघराज सिंह से ई.डी. का संपर्क नहीं हो पाया था। मेघराज के संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई, लेकिन वो नहीं मिला था। उल्लेखनीय है कि, प्रदेश में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2020 में सियासी संकट के वक्त मेघराज सिंह के जैसलमेर स्थित सूर्यगढ़ होटल में कांग्रेस नेताओं की बाड़ेबंदी की गई थी। तभी से ये ग्रुप जांच एजेंसियों की नजर में था।

कर्नाटक की...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सेवाएं ली थीं। प्रधानमंत्री मोदी तक ने अपने "विज़न-2024" का ब्ल्यू प्रिंट तैयार करवाने में बी.सी.जी. की मदद ली थी। उन्होंने आगे बताया कि राज्य सरकारें व एन.जी.ओ. भी फीडबैक व सूचना प्राप्त करने तथा अपने सिस्टम में सुधार की नवीनतम तकनीकों को लेकर उनकी सलाह लेते हैं। राव ने कहा कि "यदि विजेन्द्र बेवकूफी भरी बातें करते हैं तो सिर्फ इसलिए कि उनमें ज्ञान की कमी है। हम इतना ही कह सकते हैं।" कर्नाटक की कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार ने अपनी राजस्व प्राप्तियों में इजाफा करने के सुझाव मांगने के लिए हाल ही एक कन्सलटैंसी फर्म बी.सी.जी. की सेवाएं ली हैं।

क्या टी.एम.सी. व कांग्रेस में...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मार्केट में गड़बड़ी करने के आरोपों के चलते इसके खिलाफ एस.ई.बी.आई (सेबी) से जांच कराने की मांग को लेकर संयुक्त रूप से किए जाने वाले प्रदर्शन में शामिल होने को लेकर मुम्बई में शरद पवार से मुलाकात की थी।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस गड़बड़ी के मुद्दे को उठाया था और कुछ दिन पूर्व आयोजित की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस गडबड की जांच जे.पी.सी. से कराने की मांग की थी। हालांकि टीएमसी के नेताओं ने कहा कि मुम्बई में होने वाले इस प्रदर्शन में कांग्रेस को शामिल नहीं किया जाए। अब ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले कुछ दिनों में परिस्थितियां काफी कुछ बदल गई है। हाल ही के दिनों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदम्बरम कलकत्ता के राज्य सचिवालय में मुख्य मंत्री से मिलने गए। समझा जाता है कि यहां उन्होंने ममता बनर्जी से प्रियंका के लिए वायनाड में चुनाव प्रचार करने का अनुरोध किया है। संयोगवश, अधीर रंजन चौधरी, जो पश्चिम बंगाल की मुख्य मंत्री के तथाकथित आलोचक के रूप में जाने जाते हैं, के तेवर भी अब नरम पड़ गए लगते है। कुछ दिन पहले ही चौधरी ने स्पष्ट किया था मुख्यमंत्री के साथ उनके मतभेद राजनीतिक थे, व्यक्तिगत नहीं थे। उन्होंने आगे बताया कि वर्ष 2011 में विधान सभा चुनावों से पहले उन्होंने सोनिया गांधी को सलाह दी थी कि वामपंथियों से चुनावों में मुकाबला करने के लिए टीएमसी के साथ गठबंधन कर लेना चाहिए उस समय इस बात पर जोर देकर कहा था कि बंगाल में ममता बनर्जी सबसे विश्वसनीय चेहरा हैं।

नीट पी.जी. प्रवेश...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

में अनियमितताओं की घटनाओं को देखते हुए इस परीक्षा को टालने का निर्णय लिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि परीक्षा की पूरी प्रक्रिया को जांच परखा रखा जाएगा और नई तिथियां की घोषणा जल्दी की जाएगी।

सूरसागर सांप्रदायिक उपद्रव मामला : पांच थाना क्षेत्रों में धारा 144 लगाई, 45 उपद्रवी गिरफ्तार

सूरसागर क्षेत्र में स्थित एक ईदगाह की दीवार के पास दो दरवाज़े अवैध रुप से निकाले जाने को लेकर शुक्रवार की रात बवाल हो गया था

- **मामला इतना बढ़ा कि, दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर हमला कर दिया और दुकान व ट्रैक्टर में आग लगा दी।**
- **समझाइश कर रहे पुलिसकर्मियों को भी चोटें आईं, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पथराव में चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाने के एस.एच.ओ. नितिन दवे भी घायल हो गए।**

जोधपुर, 22 जून (कासं)। शहर के सूरसागर क्षेत्र में ईदगाह की दीवार के पास दो दरवाजे अवैध रुप से निकाले जाने को लेकर शुक्रवार की रात हुए बवाल के बाद शनिवार को स्थिति तनावपूर्ण मगर कंट्रोल रही। पुलिस ने सख्ती करते हुए सूरसागर, प्रतापनगर, प्रतापनगर सदर, देव नगर और राजीव गांधी नगर थाना क्षेत्र में 22 जून सुबह छह बजे से आगामी आदेश तक धारा 144 लगाई है।

डीसीपी आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि वृत प्रतापनगर के पांच थाना क्षेत्रों में धारा 144 लगाई गई है। शुक्रवार रात उपजे सांप्रदायिक तनाव के बाद पुलिस अब तक 200 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर 45 उपद्रवियों को गिरफ्तारी कर चुकी है। पुलिस के आला अधिकारी कल रात से ही सूरसागर क्षेत्र में डेरा डालकर बैठे हैं और क्षेत्र में आरएसी और एसटीएफ की बटालियन पुलिस जाब्ते के साथ तैनात है।

जानकारी के अनुसार शुक्रवार रात को मावडियों की घाटी क्षेत्र में स्थित एक ईदगाह परिसर में अवैध रास्ता खोलने के विवाद को लेकर दो पक्षों में बढ़े विवाद ने हिंसा का रूप ले लिया था। मौके पर जमकर कांच की बोतलें फेंकी गई और पत्थरबाजी की गई। एक दुकान को जला दिया गया। बवाल की सूचना मिलते ही पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने मौके पर पहुंच स्थिति को नियंत्रित किया। वहीं, प्रशासन ने निगम की टीम को बुलाकर मौके से कांच और पत्थर हटवाए। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है। पुलिस फोर्स इलाके में गश्त कर रही है। लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। सूरसागर क्षेत्र में हुए साम्प्रदायिक तनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने जोधपुर को अपनायत का शहर बताते हुए दोनों पक्षों से की शांति बनाए रखने की अपील की।

शहर विधायक अतुल भंसाली और सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी ने भी घटना स्थल पर पहुंच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। घटना के बाद पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने अलग-अलग गली मोहल्ले में मार्च किया। आमजन और पुलिस पर पथराव करने वाले उपद्रवियों की पुलिस ने धरपकड़ करनी शुरू की तो आरोपियों के परिवार जनों ने आक्रोश जताया। एडीसीपी नरपत और निशांत, लाभूराम व राजेन्द्र दिवाकर भी मौके पर है। बताया जाता है कि ईदगाह का गेट निकालने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद आगजनी-पथराव में बदल गया। मामला इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर हमला कर दिया और दुकान व ट्रैक्टर में आग लगा दी। इस बीच समझाइश कर रहे पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और करीब 15 आरोपियों को हिरासत में लिया। पथराव में चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाने के एस.एच.ओ. नितिन दवे भी घायल हो गए।

एन.टी.ए. प्रमुख को सरकार ने पद से हटाया

- **केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने पेपर लीक की जांच एन.टी.ए कार्यप्रणाली में कमियों को ढूंढने एवं परीक्षाओं सुधार के सुझाव देने उच्चस्तीय समिति गठित की।**
- **इस समिति का प्रमुख इसरो के पूर्व प्रमुख डॉ. के राधाकृष्णन को बनाया गया है।**

नई दिल्ली, 22 जून। नीट-यू.जी और यू.जी.सी.-नेट परीक्षाओं के आयोजन में अनियमितताओं के आरोपों के मद्देनजर नैशनल टैस्टिंग एजेंसी के प्रमुख सुबोध कुमार सिंह को शनिवार रात उनके पद से हटा दिया गया। उन्हें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में प्रतीक्षा पर रखा गया है। केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नियमित एन.टी.ए. प्रमुख की नियुक्ति होने या अगले आदेश तक उनके स्थान पर 1985 बैच के सेवानिवृत्त अधिकारी प्रदीप सिंह करोला को नियुक्त किया गया है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एन.टी.ए.) का शीर्ष नेतृत्व प्रतियोगी परीक्षाओं-नीट और नेट में कथित अनियमितताओं को लेकर जांच के दायरे में है। पेपर लीक को अब कैसे रोका जाए पेपर लीक, क्या होने चाहिए सुधार? इसको लेकर एक समिति गठित की गई है। शिक्षा मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि उसने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एन.टी.ए.) के माध्यम से परीक्षाओं का पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पूर्व प्रमुख के. राधाकृष्णन के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। डॉ. के राधाकृष्णन आईआईटी कानपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के वर्तमान अध्यक्ष हैं।

पैनल में दिल्ली स्थित एम्स के पूर्व निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया, हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति बी.जे. राव, आईआईटी दिल्ली में छात्र मामलों के डीन आदित्य मित्तल और आईआईटी मद्रास के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के पूर्व प्रोफेसर राममूर्ति के. शामिल हैं।

मु.मंत्री नायडू ने जगन मोहन रेड्डी की पार्टी का कार्यालय ध्वस्त करवाया

अमरावती, 22 जून। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाय.एस. जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाय.एस.आर.सी.पी. का कार्यालय शनिवार सुबह विजयवाड़ा के ताडेपल्ले जिले में ध्वस्त कर दिया गया। ऑफिस को गिराने के लिए बुलडोजर का सहारा लिया गया। इसके तुरंत बाद वाय.एस.आर.सी.पी. ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी पर प्रतिशोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। वाय.एस.आर.सी.पी. के अनुसार, सत्तारुढ़ तेलगू देशम पार्टी (टी.डी.पी.) प्रतिशोध की राजनीति कर रही है। वाय.एस.आर.सी.पी. ने हाईकोर्ट का दरवाया खटखटाया है।

भजनलाल पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने...

- **यही स्थिति तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह क्षेत्र जोधपुर व शांति धारीवाल के गृह नगर कोटा की हैं, जहां भारी अतिक्रमण की घटनाएं हुई हैं।**
- **इसके विपरीत मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार ने अपने क्षेत्र सांगानेर में 100 फीट सैक्टर रोड को लगभग अतिक्रमण मुक्त कर दिया, किसी भी तरह के राजनैतिक दबाव में आए बिना।**

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

टुकडे करके जब जयपुर ग्रेटर और जयपुर हैरिटेज नगर निगम बनाया गया, तो परकोटे का अधिकांश एरिया हैरिटेज निगम में था, हैरिटेज निगम के चारों विधायक रफीक खान, अमीन कागजी, महेश जोशी और प्रताप सिंह खाचरियावास निगम में वर्चस्व बनाने के लिए अपने-अपने चहेते पार्षदों को बिल्डिंग, राजस्व, अतिक्रमण और लाइसेंस से जुड़ी समितियों को चेयरमैन बनाना चाहते थे, पर कांग्रेस महापौर मुनेश गुर्जर भी अपनी पावर किसी के साथ साझा नहीं करना चाहती। नतीजन "चेयरमैनशिप" की इस लड़ाई में पार्षद और कांग्रेस के विधायक उलझ कर रह गए, इसलिए अवैध निर्माणों पर कार्रवाई नहीं हुई।

गहलोत सरकार में कांग्रेस के विधायकों ने अपने अपने नगर निगम जोन ऑफिस में उपायुक्त से लेकर बिल्डिंग शाखा के अफसर भी अपनी पसंद के ही लगाए, इसलिए अतिक्रमणों की बाढ़ आ गई। जयपुर ही नहीं जोधपुर और कोटा में भी अतिक्रमण हटाने की कोई बडी कार्रवाई पिछले 5 साल में नहीं हुई। वर्तमान में भाजपा सरकार के नेतृत्व में जयपुर शहर के तमाम प्रमुख रास्तों टोंक रोड, मानसरोवर, गोपालपुरा बायपास, सिरसी रोड, कालवाड़ रोड, झोटवाड़ा, स्टेशन रोड, कलेक्ट्री से एम.आई.रोड, चांदपोल रोड, जयपुर परकोटा, आदर्श नगर, राजापार्क इलाके में अवैध अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरु होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल अपने चुनाव क्षेत्र सांगानेर से कर चुके हैं।

जे.डी.ए. प्रशासन द्वारा गत 18 जून से हीरा पथ बी 2 बाईपास न्यू सांगानेर रोड से वन्देमातरम् मार्ग तक प्रस्तावित 100 फीट सेक्टर रोड में करीब 2.5 कि.मी. तक रोड सीमा में किये गये अवैध अतिक्रमणों हटाया जा रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट भी जयपुर शहर में अवैध अतिक्रमण हटाने का एक्शन प्लान जेडीए और नगर निगम से मांग चुका है। जे.डी.ए. के मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन महेंद्र कुमार शर्मा के मुताबिक 18 जून को पृथ्वीराज नगर (दक्षिण), सभी उपनियंत्रक प्रवर्तन और ज़ोन 1, 8 व 14 के प्रवर्तन अधिकारियों ने वन्देमातरम् चौराहा से हीरापथ बी 2 बाईपास, न्यू सांगानेर रोड की दोनों तरफ तक करीब 1 कि.मी.के दायरे में मकान, दुकान व बाउण्ड्रीवाल एवं अस्थाई झुग्गी-झोपडियों के 85 अतिक्रमणों को जेसीबी, पोकलेण्ड मशीन व लोखण्डा गैस कटर की सहायता से हटाया।

इसके बाद 19 जून को इस कार्यवाही को जारी रखते हुए करीब 800 मीटर आगे तक रोड सीमा में लगभग 70 मकान-दुकानों के किये गये अवैध कब्जों-अतिक्रमणों को ध्वस्त किया। 20 जून को भी करीब 700 मीटर दूरी में लगभग 70 मकान-दुकानों के किये गये अवैध कब्जों-अतिक्रमणों को हटाया। अब तक कुल 251 में से लगभग 225 कब्जे-अतिक्रमण इन तीन दिनों में हटाए गए हैं, शेष पर कार्यवाही जारी है। न्यू सांगानेर रोड पर हो रही यह कार्रवाई, जयपुर शहर के सभी विधानसभा क्षेत्रों में बसने वाले अतिक्रमियों को स्पष्ट चेतावनी के तौर पर देखी जा रही है, जिसका सीधा सा मैसेज है कि "अतिक्रमण करने वालों को भजनलाल सरकार किसी सूरत में नहीं बख्शने वाली।"

सरकार ने राजधानी जयपुर में अतिक्रमणों को हटाने की कवायद शुरु कर दी है। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने निर्वाचन क्षेत्र सांगानेर से ही की है। गत 19 जून को सांगानेर में 251 अतिक्रमणों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया।

नाबालिग से बार-बार...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

3.25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस प्रकरण में अन्य आरोपी रिछपाल, कृष्णा, सुरज्ञान और घनश्याम के खिलाफ अलग से ट्रायल चल रही है। अपराध में दीपक और मुकेश की भूमिका को लेकर जांच लंबित है। अदालत ने कहा कि अभियुक्तों ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म जैसा घृणित अपराध किया उसे ब्लैकमेल कर पैसे और गहने हड़प लिए। अभियुक्तों ने पीड़िता को मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक आघात पहुंचाया है। इसलिए अभियुक्तों के खिलाफ नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने बताया कि घटना को लेकर पीड़िता ने 26 सितंबर, 2019 को रेनवाल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि पवन कुमार ने चार साल पहले उसके भाई से जान-पहचान की थी। इसके तीन माह बाद पवन उसे किसी खग बाबा के यहां मिला और वहां से बहला-फुसलाकर ले गया और दुष्कर्म के बाद वीडियो बना लिया। इसके बाद पवन ने उसके साथ कई बार संबंध बनाए। वहीं कुछ दिनों बाद हंसराज से भी दुष्कर्म कराया।

हंसराज ने भी वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया और उसकी मां व दादी के सारे जेवरात व दस हजार रुपए भी ऐंठ लिए। रिपोर्ट में कहा गया कि अभियुक्तों ने उसे कृष्णा, घनश्याम, छोटू और दीपक सहित अन्य लोगों के सुपुर्द भी किया उन्होंने भी उसके साथ दुष्कर्म किया तथा उसके मोबाइल नंबर कई दूसरे लोगों को भी दे दिए। अब अभियुक्त उसकी छोटी बहन से संबंध बनवाने के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किए।

इंडिया गठबंधन...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कार्यकाल ज्यादा है। संसदीय कार्य मंत्री किरेण रिजीजू ने बताया कि महताब को इसलिए इस पद के लिए चुना गया है क्योंकि निचले सदन के सदस्य के रूप में उनका कार्यकाल निर्बाध रूप से सबसे लम्बा रहा है।

रिजीजू ने खुलासा किया कि यद्यपि सुरेश आठ बार के सांसद हैं परन्तु वे 1998 से 2004 तक लोकसभा के सदस्य नहीं थे इसलिए संसद के निचले सदन में उनका कार्यकाल निर्बाध नहीं रहा है।

कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने आठ बार के संसद सदस्य के. सुरेश को प्रो-टैम नहीं बनाकर सात बार के सांसद महताब को प्रो-टैम स्पीकर के लिए चुनकर "संसदीय परम्पराओं को नष्ट" किया है।

भाजपा ने...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उठाते हुए अवैध शराब करोबार को बढ़ावा देने में राज्य सरकार की कथित भूमिका को लेकर मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के इस्तीफे की मांग की।

कल्लाकुरिची के कलैक्टर ने बताया कि "इस प्रकरण में अब तक सात जने गिरफ्तार किए गए हैं और इस केस को तमिलनाडू पुलिस की सी.बी.आई.-सी.आई.डी. शाखा को सौंप दिया गया है। पीड़ितों को अच्छा से अच्छा उपचार दिया जा रहा है। शुरुआत में स्पेशल डॉक्टर्स काम पर लगाए गए। विभिन्न मैडिकल कॉलेजों के करीब 56 डॉक्टर्स को बीमारों के उपचार में लगाया गया है। कई पीड़ित, जिन्हें सांस लेने में दिक्कत थी, अब रिकवर हो चुके हैं।

मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि इस दुखान्तिका में जिन बच्चों ने अपने एक या दोनों अभिभावकों को खोया है, राज्य सरकार उनकी शिक्षा और हॉस्टल का खर्च वहन करेगी। उन्होंने इस दुखान्तिका के प्रत्येक मृतक के परिवार को 10 लाख रूपए और उपचाररत लोगों के लिए प्रत्येक 50 हजार रूपए देने के घोषणा भी की है।

उल्लेखनीय है कि गत 19 जून को हुए इस हादसे में एथेनॉल मिश्रित अवैध शराब पीने के बाद 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। तमिलनाडू सरकार मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व जज बी. गोकुलदास की अध्यक्षता में न्यायिक जांच का आदेश दिया है।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908